ISSN: 0973-0583

समावेशी और विविधता को प्रोत्साहित करने वाली परीक्षा प्रणाली

डॉ0 पीयूष प्रभात
प्राचार्य, भुवन मालती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मोतीहारी

सार

आज की शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य केवल ज्ञान का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि हर छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं और पृष्ठभूमि की विविधता को स्वीकार करते हुए समावेशी वातावरण बनाना है। समावेशी एवं विविधता को प्रोत्साहित करने वाली परीक्षा प्रणाली इस विचार को केंद्र में रखती है कि शिक्षा सभी के लिए है। चाहे वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई या सांस्कृतिक रूप से भिन्न क्यों न हो। इस प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली पारंपरिक परीक्षा पद्धति से आगे बढ़कर निरंतर और व्यापक मूल्यांकन (CCE) योग्यता आधारित मूल्यांकन और प्रदर्शन आधारित गतिविधियों को अपनाती है। यह सभी छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए समान अवसर देती है और शिक्षा को केवल अंक आधारित न रखकर सीखने की प्रक्रिया का विस्तार बनाती है।

भूमिका:

शिक्षा न केवल ज्ञान का साधन है, बल्कि समाज को एक दिशा देने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति भी है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि समावेशी विकास सुनिश्चित करना भी है। समावेशिता और विविधता शिक्षा के मूल स्तंभ हैं, और परीक्षा प्रणाली को इन सिद्धांतों के अनुरूप बनाना आवश्यक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परीक्षा एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। लेकिन यह देखने योग्य है कि क्या मौजूदा परीक्षा प्रणाली सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को समान रूप से संबोधित कर रही है? क्या यह प्रणाली विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और शारीरिक परिस्थितियों से आए छात्रों को एक ही मानक पर आंक कर न्याय कर पा रही है?

यह पेपर इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है और एक ऐसी परीक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल देता है जो समावेशिता और विविधता को न केवल स्वीकार करे, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी करे।

समावेशिता और विविधता का आशय

समावेशिता का तात्पर्य

समावेशिता का अर्थ है सभी छात्रों को, चाहे वे किसी भी वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र या विशेष आवश्यकताओं वाले हों, शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर देना। यह शिक्षा में समानता, सम्मान और सहभागिता को बढ़ावा देता है।

विविधता का महत्व

विविधता (Diversity) का तात्पर्य है समाज में मौजूद विभिन्न जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, लिंग, अमानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव लगातार दबाव, तुलना और प्रतियोगिता के कारण छात्र मानसिक तनाव का सामना करते हैं, जिससे आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ रही हैं।

समावेशी परीक्षा प्रणाली की आवश्यकता

प्रत्येक छात्र की क्षमता का मूल्यांकन,

प्रत्येक छात्र की सीखने की क्षमता, रुचि और शैली अलग होती है। समावेशी परीक्षा प्रणाली इन सभी को ध्यान में रखती है और उन्हें उचित अवसर देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका

नई शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी और

विविधता-आधारित शिक्षा की नींव रखी है। इसमें 'मल्टीपल इंटेलिजेंस' सिद्धांत को मान्यता दी गई है, जो मानता है कि प्रत्येक छात्र अलग तरह से बुद्धिमान होता है। कोई भाषाई, कोई गणनात्मक, कोई सांगीतिक, तो कोई शारीरिक।

समावेशी और विविधातापूर्ण परीक्षा प्रणाली की विशेषताएँ

बहुविध मूल्यांकन पद्धति

- लिखित, मौखिक, प्रोजेक्ट, केस स्टडी, गतिविधि-आधारित मूल्यांकन।
- इससे छात्रों की वास्तविक समझ और कौशल का मूल्यांकन हो पाता है।
- भाषा का लचीलापन।
- परीक्षा को सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना।
- छात्रों को अपनी मातृभाषा में उत्तर देने का अवसर देना।
- तकनीकी समावेशन।
- विशेष रूप से सक्षम छात्रों के लिए स्क्रीन रीडर, ब्रेल, वॉयस-टू-टेक्स्ट जैसी तकनीकों का उपयोग।
- समय और संरचना में लचीलापन।
- विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को अतिरिक्त समय, सहायक लेखकों की सुविधा।
- प्रश्नों की जटिलता और संख्या में विकल्प देना।
- सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान
- मूल्यांकन में स्थानीय परिप्रेक्ष्य और संदर्भ आधारित सवाल।
- केस स्टडी और प्रैक्टिकल प्रश्नों में विविधताओं को स्थान देना।

अंतरराष्ट्रीय उदाहरण

फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली

फिनलैंड में छात्रों की परीक्षा प्रणाली उनकी व्यक्तिगत प्रगति के आधार पर होती है। वहाँ छात्रों को ग्रेडिंग के बजाय फीडबैक आधारित मूल्यांकन दिया जाता है। यह प्रणाली समावेशी और तनाव-मुक्त मानी जाती है।

कनाडा और आस्ट्रेलिया

इन देशों में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए कस्टम मूल्यांकन मॉडल तैयार किए जाते हैं। वहाँ "Individual Education Plans (IEP)" बनाए जाते हैं।

भारत में सुधार की दिशा

- नीति स्तर पर परिवर्तन।
- सभी बोर्डों (NEP 2020) के अनुसार परीक्षा में लचीलापन देना चाहिए।
- दिव्यांग छात्रों के लिए UGC और अन्य संस्थानों को दिशा-निर्देश लागू करने चाहिए।

शिक्षकों का प्रशिक्षण

- शिक्षकों को समावेशी मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के साथ व्यवहार और मूल्यांकन में सहानुभूति विकसित करनी चाहिए।
- तकनीकी उपयोग को बढ़ावा।
- डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कर छात्रों की विविध जरूरतों को संबोधित करना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित करना होगा।

सामाजिक जागरूकता

- समाज को समझाना होगा कि परीक्षा केवल अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और कौशल के विकास का साधन है।
- अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी भी जरूरी है।

निष्कर्ष:

यह शोध इस बात पर केंद्रित है कि समावेशी मूल्यांकन कैसे एक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और प्रेरणादायक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करता है, जो छात्रों में आत्मविश्वास, समानता और सहभागिता की भावना को बढ़ावा देता है। यह अध्ययन विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों जैसे एनसीईआरटी की स्थिति पत्र, नई शिक्षा नीति 2020 तथा यूनेस्को और OECD रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी और विविधता-आधारित शिक्षा की नींव रखी है। इसमें 'मल्टीपल इंटेलिजेंस' सिद्धांत को मान्यता दी गई है, जो मानता है कि प्रत्येक छात्र अलग तरह से बुद्धिमान होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. राजीव तिवारी 2021, भारतीय शिक्षा में मूल्यांकन प्रणाली प्रकाशक-विनय प्रकाशन, लखनऊ
2. भारत सरकार (2020) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रकाशक-शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
3. ब्लैक, पॉल एवं विलियम, डिलन (1998) मूल्यांकन एवं कक्षा शिक्षण।
4. पीटर मिटलर (2000) समावेशी शिक्षा की ओर कार्य करना- सामाजिक संदर्भ-प्रकाशक : रुटलेज
5. NCERT (2005) परीक्षा सुधार पर स्थिति पत्र, प्रकाशक : NCERT, नई दिल्ली।
6. मापन और मूल्यांकन, राकेश कुमार (2010) बी0एल0 प्रिंटर्स दिल्ली।

✦✦✦